

शिक्षा से संबंधित लेख



Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co



उच्च शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता के पश्चात, 1935 अधिनियम मॉडल को नहीं छेड़ा गया था और शिक्षा भी इसी तरह जारी रही। हालाँकि, शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने कहा कि हालांकि "केंद्रीय नियंत्रण" संभव नहीं था, "केंद्रीय मार्गदर्शन" सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1948 में डॉ एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में हुई थी जो अध्यक्ष थे। अंतरिम सिफारिश के मुताबिक शिक्षा समवर्ती सूची में होनी थी। लेकिन, संविधान सभा ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

बाद में 1976 में 42 वें संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया। 1976 में, संविधान ने अपने कई मौलिक प्रावधानों में संशोधन किया। भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों के साथ निहित किया गया है।

इन शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की सूची नीचे दी गई हैं :

1. नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा:

यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को चौदह साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इस मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की संपूर्ण प्रगति चल रही है। वितीय सहायता के साथ, उम्मीद है कि सदी के अंत तक, हम इसे प्राप्त कर सकते हैं।

2. अल्पसंख्यकों की शिक्षा:

संविधान अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और निर्देशित करने का अधिकार है। यह धर्म और भाषा के प्रति किसी भी पक्षपात के बिना किया जाएगा।

राज्य वितीय सहायता प्रदान करने में किसी भी संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति खरीदने के लिए निर्धारित की गई निश्चित राशि प्रतिबंधित नहीं की जाएगी।

3. कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा: कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 15, 17 और 46 की स्थापना की गई। कमजोर वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख करते हैं।



अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। भारतीय समाज के कमजोर वर्ग को संस्थानों में उनके लिए दिए गए विशेष आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आर्थिक और शैक्षिक विकास संघीय सरकार की जिम्मेदारी है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें सभी अन्याय और शोषण से बचाया जाना चाहिए।

4. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा :

भारत में, चाहे अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद की शिक्षा के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। **अनुच्छेद 25 (1) के** अंतर्गत, भारत के नागरिक को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म के मानने, अभ्यास और प्रचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 28 (1) के अनुसार, कोई भी संस्था जो राज्य निधि से पूर्णतः अनुरक्षित है, कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 28 (2) के अनुसार, यदि कोई संस्थान किसी ट्रस्ट के किसी बंदोबस्ती के तहत स्थापित किया जाता है, तो (1) खंड उन पर लागू नहीं होगा, हालांकि वे राज्य द्वारा वित्त पोषित हो सकते हैं।

अनुच्छेद 28 (3) में कहा गया है कि "राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।"

अनुच्छेद 30 के अनुसार, राज्य राज्य द्वारा या राज्य निधि द्वारा बनाए गए संस्थानों के लिए सहायता प्रदान करने में धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

5. शैक्षिक संस्थानों में अवसरों की समानता:

अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि "किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या राज्य कोष से सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।"

इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों के अनुसार किसी को भी समान शिक्षा और गुणवता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और सभी के लिए समान अवसरों के बिना यह व्यर्थ है। कोठारी आयोग 1964-66 ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार लोगों के लिए समान अवसरों और भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी उत्तरदायी है।



6. मातृभाषा में निर्देश:

भारत विभिन्न भाषाओं, लिपियों और बोलियों वाला देश है। अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना भारत में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 350 (ए) के तहत, "यह हर राज्य और हर स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।" इसका अर्थ यह है कि हर क्षेत्र में अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा दी जा सकती है। 1953-53 के माध्यमिक चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि क्षेत्रीय भाषा माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान के रूप में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

7. हिंदी का प्रचार:

भारतीय संविधान ने हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना कर्तव्य है। हिंदी भाषा देश भर में एक बड़ी कड़ी के रूप में भी काम करती है। यह एक ऐसी विधि भी प्रतीत हुई है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निहित है।

8. उच्च शिक्षा और अनुसंधान:

संसद के पास विशिष्ट अधिकार हैं जिनका उल्लेख एंट्री 63, 64, 65 और 66 में किया गया है। केंद्रीय सूची की एंट्री 63 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और इस संविधान के प्रारंभ में ज्ञात किसी अन्य संस्था को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाता है।

9. महिलाओं की शिक्षा:

जब देश की महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो भारतीय शिक्षा प्रणाली ने व्यापक विकास दिखाया है। महिलाओं को अनुच्छेद 15 (1) के तहत बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 15 (3) कहता है, "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।" शिक्षा एक ऐसी विधा बन गई है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को बदल देती है।

10. केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा:

संविधान के अनुच्छेद 239 में कहा गया है, "संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।" इसका अर्थ यह है कि केंद्रशासित



प्रदेश के लोग भी वैसी ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भारत का कोई अन्य भाग करता है।

11. विदेशी देशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध:

संघ सूची की एंट्रि 13 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में प्रतिभागिता और उसके बाद लिए गए निर्णयों को लागू करना। छात्र शैक्षिक सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं जो बिना किसी भेदभाव या प्रतिबंध के दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं।

प्रश्न 1 : निम्नितिखित में से किसने शिक्षा को समवर्ती सूची का हिस्सा बनाने में अग्रणी कदम उठाया?

A. मौलाना आज़ाद

B. पंडित जवाहरलाल नेहरू

C. डॉ. बी. आर. अंबेडकर

D. डॉ. एस राधाकृष्णन

उत्तर: D. डॉ. एस राधाकृष्णन

समाधान : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. एस. राधाकृष्णन ने अपने कार्यकाल के दौरान सिफारिश की कि शिक्षा समवर्ती सूची में होनी चाहिए।

प्रश्न 2 : देश भर में हिंदी भाषा के प्रचार का एक कारण निम्नलिखित में से क्या है?

A. अंग्रेजी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना

B. राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा देना

C. हिंदी एक कड़ी के रूप में कार्य करती है

D. B और C दोनों

उत्तर: D. B और C दोनों

समाधान : हिंदी भाषा पूरे देश में एक बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करती है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

प्रश्न 3 : EHEI का पूर्ण रूप क्या है?

A. उच्च शिक्षा सूचकांक में निष्पक्षता



- B. उच्च शिक्षा सूचकांक में समानता
- C. छिपी ह्ई शिक्षा आय में समानता
- D. उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता

उत्तर : A. उच्च शिक्षा सूचकांक में निष्पक्षता

समाधान : EHEI उच्च शिक्षा सूचकांक में निष्पक्षता के लिए है। शिक्षा में निष्पक्षता का अर्थ है कि व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितियाँ जैसे लिंग, जातीय मूल या पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक क्षमता प्राप्त करने में बाधा नहीं हैं।

प्रश्न 4 : निम्नलिखित में से किसे कलकता विश्वविदयालय आयोग के रूप में जाना जाता है?

- A. उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग
- B. मैकाले आयोग
- C. सैडलर आयोग
- D. हंटर आयोग

उत्तर: C. सैडलर आयोग

समाधान : कलकता विश्वविद्यालय आयोग को अपने अध्यक्ष डॉ. माइकल ई. सैडलर, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पर सैडलर आयोग के रूप में भी जाना जाता है।

प्रश्न 5 : निम्नलिखित में से NUEPA द्वारा किसका समाधान किया गया है?

- A. शैक्षिक समानता
- B. शैक्षिक उपलब्धता
- C. शैक्षिक योजना
- D. शैक्षिक पर्यवेक्षण

उत्तर : C. शैक्षिक योजना

समाधान : NUEPA का अर्थ राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान है। यह शैक्षिक योजना से संबंधित है।

www.gradeup.co



प्रश्न 6 : निम्नलिखित में से कौन UGC के पहले अध्यक्ष थे?

A. शांतिस्वरुप भटनागर

B. प्रो. यशपाल

C. डॉ. डी. एस कोठारी

D. एम. एम. शर्मा

उत्तर: A. शान्तिस्वरुप भटनागर

समाधान : शान्तिस्वरुप भटनागर UGC के पहले अध्यक्ष थे।

प्रश्न 7 : API का पूर्ण रूप क्या है ?

A. शैक्षणिक व्यक्तित्व सूचकांक

B. अकादमिक व्यक्तित्व संकेतक

C. शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक

D. शैक्षणिक भुगतान किस्त

उत्तर: C. अकादमिक प्रदर्शन संकेतक

समाधान : API अकादिमिक प्रदर्शन संकेतक के लिए है। यह उस उपाय से संबंधित है जो एक छात्र, शिक्षक या एक संस्थान की वृद्धि को दूर करता है।

प्रश्न 8 : राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है

A. 9 जनवरी

B. 5 सितंबर

C. 12 जुलाई

D. 11 नवंबर

उत्तर: D. 11 नवंबर

समाधान : भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है।

www.gradeup.co



प्रश्न 9 : निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय है?

- A. डॉ. बीआर अंबेडकर म्कत विश्वविद्यालय
- B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
- C. नालंदा विश्वविद्यालय
- D. दिल्ली विश्वविद्यालय

उत्तर: A. डॉ. बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय

समाधान : 26 अगस्त 1982 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में डॉ. बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यह भारत में 'पहला मुक्त विश्वविद्यालय' है।

प्रश्न 10 : इग्नू की स्थापना वर्ष में हुई थी

- A. 1993
- B. 2001
- C. 1991
- D. 1985

उत्तर : D. 1985

समाधान : इग्नू को सितंबर 1985 में स्थापित किया गया था।



Constitutional Provisions Related to Higher Education

After Independence, the 1935 Act model was not disturbed and the education continued to be the same. However, Maulana Azad, the education minister stated that though the "Central Control" was not possible, "Central Guidance" must be ensured.

The University Education Commission was appointed in the year 1948, under Dr. S. Radhakrishnan who was the chairman. According to the interim recommendation, education was to be in the concurrent list. But, the Constituent Assembly did not accept the recommendation.

Later according to the 42nd amendment in 1976 education was made a part of the concurrent list. In 1976, the constitution made amendments in many of its fundamental provisions. According to the Constitution of India, the Central Government has been vested with responsibilities related to higher education.

These are the list of Constitutional Provisions relating to education are given below:

1. Free and Compulsory Education:

This comes under **Article 45** of the Directive Principles of State Policy. This states that all the children must have free and compulsory education until the age of fourteen. It also mentions that this is a joint responsibility of the Centre as well as the States. The entire progress of this free and compulsory education is under progress. With financial aids, hopefully, by the end of the century, we can achieve it.

2. Education of Minorities:

By **Article 30**, the Constitution provides the minorities to establish and administer educational institutions. According to this article, all minorities have



the right to set up and direct the educational institutions of their choice. This will be done without any partiality for religion and language.

The State shall not discriminate against any institution in providing financial aid. They should ensure that the fixed amount determined to procure the property shall not be restricted.

3. Education for Weaker Sections:

To safeguard the weaker sections' educational interests the **Article 15, 17 and 46** were established. The weaker sections refer to the socially and educationally backward classes and the scheduled castes and scheduled tribes.

Article 15 prevents discrimination based on religion, race, caste, race, sex or place of birth. The weaker classes of the Indian society cannot be denied of the special reservations held for them in the institutions.

Under **Article 46**, the economic and educational development of the scheduled caste and the scheduled tribe is the responsibility of the federal government.

This means that they should be protected from all the injustice and exploitation.

4. Secular Education:

In India, whether the minorities are based on Religion or Language, they must be given full rights for the education of their choice. Under **Article 25 (1)**, the citizen of India is free to have the freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate the religion.

According to **Article 28(1)**, any institution that is maintained wholly out of the state fund shall not provide any religious instruction. But according to Article 28 (2), if an Institution is established under any endowment to a Trust the clause in the (1) shall not apply to them though they might be funded by the State.



Article 28 (3) states that "No person attending any educational institution by the state or receiving aid out of state funds, shall be required to take part in any religious instruction that may be imported in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person a minor, his guardian has given his consent thereto."

By **Article 30**, the State shall not discriminate by religion, caste, race, or language in providing aid for institutions that are maintained by the State or by the State fund.

5. Equality of Opportunities in Educational Institutions:

Article 29(1) states that "No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds, on grounds only of religion, race, caste, language or any of them."

It means that by fundamental rights no shall be denied equal education and quality is meaningless without equal opportunities or everyone. The Kothari-Commission of 1964- 66 recommended that the Central Government is responsible for equal opportunities for the people and also the weaker sections of the Indian Society.

6. Instruction in Mother Tongue:

India is a country with a variety of languages, scripts, and dialects. To study one's own mother tongue is a fundamental right in India. Under **Article 350 (A)**, "It shall be the endeavor of every state and every local authority to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups." This means that every region can have the education imparted in their mother tongue as well. The Secondary Election Commission of 1953-53 recommended that the regional



language should be the medium of instruction in secondary schools as a provision for linguistic minorities.

7. Promotion of Hindi:

The Indian Constitution has made provisions to promote Hindi as our national language. Under **Article 351**, it is the duty to promote the spread of the Hindi Language. Hindi language also serves as a large link across the country. This has also seemed to be a method that is implied to strengthen the National Unity.

8. Higher Education and Research:

The Parliament has exclusive rights that are mentioned in entries 63, 64, 65 and 66. In the **Entry 63** of the Union List, Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University, and any other institution known at the commencement of this Constitution is declared to be an Institution of National importance by the Parliament.

9. Women's Education:

Indian Education system has shown a massive evolution when it comes to the education of the women of the country. Women are provided education with no discrimination under **Article 15 (1)**. **Article 15 (3)** says "Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children." Education has become a mode that changes the status of women in society.

10. Education of the Union Territories:

Article 239 of the Constitution states, "Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union Territory shall be an administrator by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify." This means that



the people of Union Territories are also free to receive the same education just like any other part of India does.

11. Educational and cultural relations with foreign countries:

According to **Entry 13** of the Union List, participation in international conferences, associations and other bodies and implementing decisions made thereat. Students can participate in educational conferences that are conducted across the globe without any discrimination or restriction.

- Q1. Who among the following made took the pioneer step in making education a part of the concurrent list?
- A. Maulana Azad
- B. Pandit Jawaharlal Nehru
- C. Dr. B. R. Ambedkar
- D. Dr. S. Radhakrishnan

Answer: D. Dr. S. Radhakrishnan

Solution: Dr. S. Radhakrishnan, during his tenure as the chairman of the University Education Commission, recommended that education should be in the concurrent list.

- **Q2.** Which of the following is a reason for the promotion of Hindi language across the country?
- A. To discourage the use of English language
- B. To promote the integrity of the nation
- C. Hindi serves as a link
- D. Both B and C



Answer: D. Both B and C

Solution: Hindi language serves as a large link across the country. This has enabled to strengthen the national unity. Hence the correct answer is option D.

Q3. What is the full form of EHEI?

A. Equity in Higher Education Index

B. Equality in Higher Education Index

C. Equality in Hidden Education Income

D. Equity in Higher Education Institutes

Answer: A. Equity in Higher Education Index

Solution: EHEI stands for Equity in Higher Education Index. Equity in education means that personal or social circumstances such as gender, ethnic origin or family background, are not obstacles to achieving educational potential.

Q4. Which of the following is known as Calcutta University Commission?

A. National Commission on Higher Education

B. Macullay Commission

C. Saddler Commission

D. Hunter Commission

Answer: C. Saddler Commission

Solution: The Calcutta University Commission is also known as the Sadler Commission after the name of its chairman Dr. Michael E. Sadler, the Vice Chancellor of the university of Leeds.



Q5. Which of the following is dealt by NUEPA?

A. Educational equality

B. Educational availability

C. Educational planning

D. Educational supervision

Answer: C. Educational planning

Solution: NUEPA stands for National Institute of Educational Planning and Administration. It deals with educational planning.

Q6. Who among the following was the first chairman of UGC?

A. Shantiswarup Bhatnagar

B. Prof. Yashpal

C. Dr. D. S Kothari

D. M. M. Sharma

Answer: A. Shantiswarup Bhatnagar

Solution: Shantiswarup Bhatnagar was the first chairman of UGC.

Q7. What is the full form of API?

A. Academic Personality Index

B. Academic Personality Indicator

C. Academic Performance Indicator

D. Academic Paid Installment

Answer: C. Academic Performance Indicator

www.gradeup.co



Solution: API stands for Academic Performance Indicator. It deals with measure that gives away the growth of a student, teacher or an institution.

Q8. National Education Day is observed on

A. 9th January

B. 5th September

C. 12th July

D. 11th November

Answer: D. 11th November

Solution: National Education Day is celebrated every year on November 11 in

India. It is celebrated to commemorate the birth anniversary of the first

Education Minister of India, Maulana Abul Kalam Azad.

Q9. Which of the following is the first open university in India?

A. Dr B.R Ambedkar Open University

B. Indira Gandhi National Open University

C. Nalanda University

D. Delhi University

Answer: A. Dr B.R Ambedkar Open University

Solution: Dr B.R Ambedkar Open University in Hyderabad, Andhra Pradesh set up on 26th August 1982, is the 'First Open University in India.

Q10. IGNOU was established in the year

A. 1993

B. 2001

C. 1991

D. 1985

Answer : D. 1985

Solution: IGNOU was established on September 1985.